अमरीका की शिक्षा व्यवस्था में स्कूल और अध्यापन

मनीष जैन द्वारा डॉ हीथर बिग्ले से साक्षात्कार

डॉ हीथर बिग्ले अमरीका के बेसिस फ़्लेगस्टॉफ़ (BASIS Flagstaff) स्कूल में अध्यापिका हैं। उन्होंने फ़्लोरिडा विश्वविद्यालय से अँग्रेज़ी में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और उनका शोध प्रबन्ध छोटे स्तरों के सिनेमा में वैश्वीकरण, धार्मिक पहचान और महिला स्वायत्तता पर केन्द्रित था। उन्होंने मॉरमॉन (1820 में न्यूयॉर्क में जोसेफ़ स्मिथ द्वारा आरम्भ किया गया धार्मिक व सांस्कृतिक समूह), मग़रिबी (उत्तर-पश्चिमी अफ़्रीका– आज के अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिसिआ, लीबिया– के रहने वाले अरब और बर्बर समुदायों) और बॉलीवुड फ़िल्मों पर शोध लेख प्रकाशित किए हैं। अप्रैल 2019 में यह साक्षात्कार लिए जाने के दौरान डॉ हीथर बिग्ले फ़ुलब्राइट स्कॉलर के तौर पर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के स्कूल ऑफ़ एजुकेशन स्टडीज़ से जुड़ी हुई थीं। उनका ईमेल है– heather.bigley@basised.com

यह साक्षात्कार हमें न केवल एक स्कूल अध्यापक के नज़रिए से अमरीका की स्कूल व्यवस्था को समझने के लिए अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि हमारा ध्यान दुनिया भर के अलग-अलग देशों में हो रहे शैक्षिक सुधारों की वैश्विक प्रकृति की ओर भी दिलाता है जिनकी वकालत आजकल ज़ोर-शोर से की जा रही है।

मनीष : हीथर, अमरीका में मौजूद विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बारे में बताइए। उन्हें चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है और इनमें आपस में क्या अन्तर हैं ?

हीथर : देखिए, अमरीका में तीन प्रकार के स्कूल हैं : (अ) सरकारी; (ब) चार्टर व स्वतन्त्र स्कूल; और (स) निजी स्कूल (संख्या के आधार पर देखें तो इनमें बहुत बच्चे नहीं जाते हैं और इनका नामांकन केवल 10-12% तक ही है)।[1] इनमें से अधिकतर धार्मिक स्कूल हैं और उन्हें अपने धार्मिक संगठनों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। जो निजी स्कूल धार्मिक नहीं हैं, वे बहुत महँगे स्कूल हैं। निजी स्कूल ट्यूशन फ़ीस आधारित स्कूल हैं और वे सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए निर्धारित मानकों या तय की गई नीतियों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अभिभावकों को सन्तुष्ट करने के लिए वे स्कूल चाहें तो इनका पालन कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों को उनके आसपास के क्षेत्र से एकत्रित सम्पत्ति कर के आधार पर राज्य से आर्थिक सहायता और प्रति छात्र संघीय सहायता मिलती है। सरकारी स्कूल सार्वजनिक नीतियों से नियमित होते हैं। उदाहरण के लिए, ओबामा सरकार के अन्तर्गत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों को ख़ुद को ट्रांसजेण्डर कहने वाले व्यक्तियों के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था करनी पड़ी। निजी स्कूलों को ऐसा नहीं करना पड़ा। मेरा स्कूल

1. 2013-2014 का सरकारी आँकड़ा (NCES) बताता है कि अमरीका के 10% विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, निजी स्कूलों में से 69% धार्मिक स्कूल हैं [https://nces.ed.gov/blogs/nces/post/a-look-at-private-schools-and-homeschooling]। इसकी तुलना में 2016-17 में भारत में प्राथमिक स्तर पर 30.73% विद्यार्थी और कक्षा I-XII तक 31.83% विद्यार्थी सहायतारहित निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे (NIEPA 2018)।

एक चार्टर स्कूल है जिसने जेण्डर-विशिष्ट शौचालयों की जगह जेण्डर-तटस्थ शौचालयों का निर्माण किया है।

सरकारी स्कूल राज्य शासन के अधीन होते हैं और राज्य व संघ दोनों सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। राज्य और संघ का वित्तीय योगदान एक से दूसरे राज्य के लिए अलग-अलग है। जैसे– एरिज़ोना राज्य को राज्य सरकार के मुकाबले संघीय सरकार से ज़्यादा वित्त मिलता है, जो कि एक चौंकाने वाली बात है। स्थानीय स्तर पर स्कूल बोर्ड है जो एक निर्वाचित लोकतान्त्रिक निकाय है और यह तय करता है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा।

चार्टर स्कूल भी राज्य व संघ, दोनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं और यह सहायता भी हर राज्य में अलग-अलग है। इन स्कूलों को अध्यापक प्रमाणीकरण (certification) और पाठ्यचर्या मानकों के मानदण्डों को पूरा करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी अभिभावकों की माँग के अनुसार वे ऐसा कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों के विपरीत उन्हें ख़ास ज़रूरत वाले छात्रों के लिए अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति करने की भी आवश्यकता नहीं है। पारम्परिक रूप से शहरी क्षेत्रों के चार्टर स्कूल शहरी ग़रीबों पर केन्द्रित रहे हैं। उन्हें नई इमारतें बनाने और स्कूल की दूसरी ज़रूरतों जैसे कि कम्प्यूटर इत्यादि ख़रीदने के लिए अनुदान उपलब्ध है। ज़्यादा ग़रीब राज्यों में चार्टर स्कूलों के बनने की सम्भावना अधिक है जैसे कि सुदूर दक्षिण में लुइसिआना राज्य।

पारम्परिक रूप से शहरी क्षेत्रों के चार्टर स्कूल शहरी ग़रीबों पर केन्द्रित रहे हैं। उन्हें नई इमारतें बनाने और स्कूल की दूसरी ज़रूरतों जैसे कि कम्प्यूटर इत्यादि ख़रीदने के लिए अनुदान उपलब्ध है। ज़्यादा ग़रीब राज्यों में चार्टर स्कूलों के बनने की सम्भावना अधिक है जैसे कि सुदूर दक्षिण में लुइसिआना राज्य।

सरकारी स्कूलों में मुफ़्त नाश्ता, दोपहर का भोजन और मुफ़्त परिवहन संघीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं– ये कार्यक्रम चार्टर स्कूलों के लिए भी उपलब्ध हैं, पर मेरा चार्टर कॉर्पोरेशन इन प्रावधानों का लाभ नहीं उठाता है और यह स्कूल में आने वाले छात्रों की जनसांख्यिकीय संरचना को प्रभावित करता है।

मनीष : आपने अभी कहा कि आपका स्कूल मुफ़्त भोजन और मुफ़्त परिवहन की सुविधा का लाभ नहीं उठाता है और इस बात ने आपके स्कूल की जनसांख्यिकी को प्रभावित किया है। क्या आप और विस्तार से बता सकती हैं कि क्यों आपका स्कूल इन प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं करता है और यह किस प्रकार इस बात पर प्रभाव डालता है कि कौन आपके स्कूल में दाख़िले के लिए आता है?

हीथर : मैं केवल इस बात का अन्दाज़ा ही लगा सकती हूँ कि क्यों मेरा चार्टर कॉर्पोरेशन संघीय सरकार द्वारा चलाए जाते मुफ़्त भोजन और परिवहन कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है। हालाँकि, स्कूल के इस निर्णय के कारण उस छात्र आबादी को बढ़ावा मिला है जिनके अभिभावक उन्हें रोज़ाना आसानी से स्कूल छोड़ सकते हैं और वापिस घर ले जा सकते हैं (जिसका सीधा मतलब है– परिवार में कई कारों का होना, घर पर रहने वाला कोई एक अभिभावक जो उन्हें रोज़ाना स्कूल लाने और ले जाने के लिए उपलब्ध है, या फिर स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों के परिवारों का नेटवर्क) और ऐसे छात्र जो रोज़ाना अपना दोपहर का खाना घर से ला सकते हैं या ख़रीदकर खा सकते हैं। औसतन हमारे विद्यार्थी मध्यम वर्ग या उच्च-मध्यम वर्ग के परिवारों से आते हैं जो स्कूल और अध्यापक निधि में चन्दा भी देते हैं।

मनीष : क्या चार्टर स्कूलों के बीच भी अन्तर हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि अध्यापक नेतृत्व वाले चार्टर स्कूल भी हैं। वे अन्य चार्टर स्कूलों या सरकारी स्कूलों से किन मायनों में अलग हैं?

हीथर : कई चार्टर जो विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुधारने में कामयाब हुए हैं, उन्हें अफ्रीकी-केन्द्रित चार्टर कहा जाता है। अपने प्रयासों से वे उन अश्वेत विद्यार्थियों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं जिन्हें विषय-वस्तु, शिक्षण पद्धति और संस्थायी सम्बन्धों के सन्दर्भ में बहुसंख्यक ग़ोरी संस्कृति द्वारा हाशिए पर धकेला जा सकता है। अध्यापक नेतृत्व वाले चार्टर दुर्लभ हैं, लेकिन वे हैं ज़रूर और वे आशा व कोशिश करते हैं कि अध्यापक चार्टर स्कूलों को छोड़कर न चले जाएँ– जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि चार्टर में शिक्षक संघ नहीं होते, वे सरकारी स्कूलों से कम वेतन देते हैं और नए अध्यापकों को बिल्कुल न के बराबर पेशेवर समर्थन और भावनात्मक सम्बल देते हैं। इन्हीं कारणों से मेरे ख़ुद के चार्टर स्कूल ने अपने शुरुआती पाँच सालों में हर साल आधे शिक्षक खो दिए।

जैसा कि आप जानते ही हैं, मानकीकृत परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक लाना सीधे–सीधे परिवार या परिवेश की आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व से जुड़ा है। इसलिए हमारे छात्र सरकारी स्कूलों में रह गए ग़रीब छात्रों के मुक़ाबले ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं।

मनीष : चार्टर स्कूलों के बारे में उपलब्ध साहित्य उनकी स्वायत्तता पर केन्द्रित है। चार्टर स्कूल के कई समर्थक जहाँ यह तर्क देते हैं कि चार्टर स्कूल क़ानून बेहद 'लोकतान्त्रिक' हैं, वहीं आलोचकों का यह मानना है कि चार्टर स्कूल इस स्वायत्तता और चयनात्मक दाख़िले का इस्तेमाल कर सार्वजनिक शिक्षा के क्षीण संसाधनों को भी हड़प लेते हैं।[2] क्या आप बता सकती हैं कि यह स्वायत्तता किस तरह काम करती है? क्या यह सार्वजनिक शिक्षा को नुक़सान पहुँचाती है और जैसा कि चार्टर स्कूलों के आलोचक आरोप लगाते हैं कि यह सार्वजनिक शिक्षा पर ख़र्च होने वाले 'बोझ' को ख़त्म करने के लिए रास्ता तैयार करती है?

हीथर : ये आरोप छोटे शहर के मेरे अपने चार्टर स्कूल के ख़िलाफ़ भी लगाए गए हैं और जैसा कि मैं देख रही हूँ, ये काफ़ी हद तक सही भी हैं। क्योंकि हम मुफ़्त भोजन और परिवहन के लिए संघीय कार्यक्रम का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा कर हम उन विद्यार्थियों को अवरुद्ध कर रहे हैं जिन्हें कहीं ज़्यादा संस्थागत सहारे और प्रोत्साहन की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मानकीकृत परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक लाना सीधे-सीधे परिवार या परिवेश की आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व से जुड़ा है इसलिए हमारे छात्र सरकारी स्कूलों में रह गए ग़रीब छात्रों के मुक़ाबले ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। चूँकि हमारे स्कूल को प्रति विद्यार्थी संघीय वित्तीय सहायता और उसके अलावा राजकीय वित्तीय सहायता मिलती है, इसलिए आर्थिक रूप से हम स्थानीय सरकारी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा में जुटे हैं। साठ हज़ार की आबादी वाले हमारे छोटे-से शहर में एक दर्ज़न से ज़्यादा चार्टर स्कूल हैं। अगर ये विद्यार्थी केवल सरकारी स्कूलों में जा रहे होते तो वह वित्तीय सहायता सकारात्मक रूप से उन स्कूलों के हिस्से में जाती।

मनीष : भारत में पिछले एक दशक में 'नए नीति कर्मियों' (न्यू पॉलिसी एक्टर्स) ने वाउचर व्यवस्था की ज़ोर-शोर से वकालत की है। पिछले कुछ समय में जो नवीनतम बदलाव आपके देश अमरीका की

2. इन बहसों के लिए देखें वेल्स एवं अन्य (2002)।

शिक्षा नीति में हुए हैं वे क्या हैं और किस प्रकार वे आपके देश के स्कूलों को प्रभावित कर रहे हैं?

हीथर : बेट्सी डेवोस, जो अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की शिक्षा सलाहकार हैं, वाउचर[3] कार्यक्रम के विस्तार की पैरवी करती रही हैं। मेरे राज्य एरिज़ोना में रिपब्लिकन पार्टी ख़ास ज़रूरत वाले बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने के लिए वाउचर की घुट्टी पिला रही है, जहाँ इन विद्यार्थियों के लिए सच में कोई सहायता उपलब्ध नहीं है।[4] इस स्थिति में अभिभावक समावेशी शिक्षा की तलाश में बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल स्थानान्तरित करते रह जाते हैं। 'कोई बच्चा पीछे न छूटे' (No Child Left Behind, NCLB)[5] स्कूलों की प्रभावशीलता[6] को जाँचने के लिए मानकीकृत परीक्षा का आदेश देता है। मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग से आने वाले विद्यार्थी इस परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित कर पाते हैं जबकि ग़रीब क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी उतना नहीं। उन्हें आर्थिक और भावनात्मक सहारे और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। स्कूलों के बेहतर प्रदर्शन में स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था अपना योगदान निभाते हैं। अब लुइसिआना के न्यू ओरलींस शहर में, जिसकी जनसंख्या चार लाख (400,000) से ज़रा कम है, एक भी सरकारी स्कूल नहीं है– हैं तो केवल चार्टर और निजी स्कूल।[7] सरकारी स्कूल लगातार चार्टर स्कूलों को सौंपे जा रहे हैं। यह दलील दी जा रही है कि सरकारी स्कूल असफल हो रहे हैं, हम इनमें सुधार नहीं कर सकते और चार्टर स्कूल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों की

3. वाउचर कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारें परिवारों को वाउचर का प्रस्ताव देती हैं। ये वाउचर कूपन की तरह होते हैं जो यह दिखाते हैं कि सरकार का कितना पैसा छात्र पर ख़र्च हुआ होता, अगर उसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की होती। वाउचर को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है कि यह परिवारों को अपने बच्चों के लिए अपनी मनपसन्द का स्कूल चुनने की आज़ादी देता है और परिवार अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण अपने बच्चों को किन्हीं अन्य स्कूलों में भेजने की बजाय सरकारी स्कूलों में भेजने को बाध्य नहीं हैं। परिवार इन वाउचरों का इस्तेमाल निजी स्कूलों के लिए भी कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज सकते हैं। चर्च और राज्य के बीच विच्छेद के संवैधानिक अध्यादेश के बावजूद अमरीका के 14 राज्यों में छात्र इन वाउचरों का इस्तेमाल धार्मिक स्कूलों में कर सकते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि वाउचर विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बीच अपने यहाँ छात्रों को दाख़िले के लिए आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है और इस तरह उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाता है। भारत में कुछ ख़ास नीति वकालत समूह जैसे कि सेण्टर फ़ॉर सिविल सोसाइटी वाउचर प्रणाली को शुरू किए जाने की पैरवी कर रहे हैं।

4. https://www.nytimes.com/2017/04/11/us/school-vouchers-disability.html

5. जनवरी 2002 में उस वक़्त के अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू बुश ने अमरीकी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद 'कोई बच्चा पीछे न छूटे अधिनियम' पर हस्ताक्षर किए। इस अधिनियम के अन्तर्गत, अब स्कूलों को केवल पहले वाले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क़ानून के 'अनुपालन' को दर्शाना पर्याप्त नहीं था। अब उन्हें अलग-अलग उपसमूहों के असमग्र आँकड़ों (disaggregated data) के साथ बड़े पैमाने पर की जाने वाली मानकीकृत परीक्षा के परिणामों के ज़रिए अपनी जवाबदेही साबित करनी थी। इसने स्कूल के सभी पहलुओं को प्रभावित किया— क्या पढ़ाया जाएगा, शिक्षकों का चयन व नियुक्ति कैसे होगी और पैसे का आवण्टन किस प्रकार होगा? शोधकर्ताओं ने उपलब्धियों पर इसके असर, ग़ैर-परीक्षित विषयों पर लगाए गए अध्यापन समय, अध्यापकों की प्रेरणा और तनाव और इसके नस्लवादी आधारों की चर्चा की है। इन चर्चाओं के लिए देखें— हर्श (2007), स्मिथ और कोवाक्स (2011), वैल्स एवं अन्य (2002) और वुन (2014)।

6. स्कूल प्रभावशीलता आन्दोलन ज्ञान अर्जन में स्कूलों के प्रभाव का आँकड़ों की दृष्टि से मूल्यांकन करता है और इन आधारों पर स्कूलों के बीच तुलना करता है। आलोचक इस ओर इशारा करते हैं कि यह तरीक़ा स्कूल में सीखने को बहुत हद तक केवल शैक्षिक ज्ञान के आकलन और तुलनायोग्य बिन्दुओं तक घटा देता है (स्ले एवं अन्य, 1998:2)। यह नस्ली विषमता और स्कूल में ख़राब प्रदर्शन के बीच के रिश्ते और ज़्यादा बड़े राजनीतिक और नीति सन्दर्भ, जो ग़रीबी पैदा करते हैं, की ओर कोई ध्यान नहीं देता है (रिग्ले, 2013:37)।

7. https://www.theadvocate.com/new_orleans/news/education/article_9e7c55fc-0471-11e9-8c4c-e3f94b3162f1.html

बागडोर उन्हें ही सँभालने दो।[8] वहाँ कोई मध्यम वर्ग नहीं है जो इस हस्तान्तरण का विरोध कर सके क्योंकि इस वर्ग से आने वाले विद्यार्थी तो पहले ही निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। ज़ाहिर तौर पर ग़रीब अभिभावकों का स्कूल बोर्ड में बहुत कम प्रतिनिधित्व है। लुइसिआना की तुलना में वॉशिंगटन राज्य में कोई चार्टर स्कूल नहीं है। यहाँ एक बेहद मज़बूत शिक्षक संघ है और शिक्षकों को अच्छा वेतन मिलता है। वॉशिंगटन राज्य माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन का गढ़ है।[9] लेकिन यहाँ निजी स्कूल भी हैं। इन तकनीकी कम्पनियों के साथ काम करने वाले लोगों ने राजकीय स्कूलों में पढ़ाई की और सार्वजनिक शिक्षा से लाभान्वित हुए। उनके पास सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करों द्वारा एकत्रित राशि है।[10] वॉशिंगटन राज्य में जीवनयापन की लागत राष्ट्रीय अनुपात से 4.8% अधिक है : शिक्षकों की औसत आय $ 64,987 और प्रति विद्यार्थी सालाना व्यय $ 10,339 है। एरिज़ोना में, जहाँ मैं रहती हूँ, जीवनयापन की लागत राष्ट्रीय औसत से 3.8% कम है। शिक्षकों की औसत आय $ 44,284 और प्रति विद्यार्थी सालाना व्यय $ 8,131 है। रोचक बात यह है कि एरिज़ोना जीवनयापन व्यय की दृष्टि से देश में 25 वें स्थान पर आता है लेकिन शिक्षा में निवेश की दृष्टि से वह 48वें स्थान पर है।

सरकारी स्कूल लगातार चार्टर स्कूलों को सौंपे जा रहे हैं। यह दलील दी जा रही है कि सरकारी स्कूल असफल हो रहे हैं, हम इनमें सुधार नहीं कर सकते और चार्टर स्कूल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों की बागडोर उन्हें ही सँभालने दो। वहाँ कोई मध्यम वर्ग नहीं है जो इस हस्तान्तरण का विरोध कर सके।

मनीष : सरकार की नीतियों से आपका स्कूल किस प्रकार प्रभावित होता है?

हीथर : मेरे अपने चार्टर स्कूल कॉर्पोरेशन के 27 स्कूल हैं जो मध्यम वर्ग और शहरी अमीरों पर लक्षित हैं। इनमें से 15 स्कूल एरिज़ोना, लुइसिआना, टैक्सस और वॉशिंगटन डीसी में हैं और एक निजी स्कूल शाखा कैलिफ़ोर्निया में शुरू की गई है। मेरा अपना चार्टर स्कूल कॉर्पोरेशन प्राप्त की गई कुल फण्डिंग का 14% 'प्रबन्धन फ़ीस' के तौर पर ले लेता है। जब मैं एरिज़ोना के अन्य शिक्षकों से, दूसरे राज्यों के शिक्षकों से और अपने दोस्तों से, जिनके साथ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, अपनी तुलना करती हूँ तो पाती हूँ कि मेरे वेतन के कम होने का यह एक कारण है।

मनीष : कुछ समय पहले आपने वॉशिंगटन में शक्तिशाली शिक्षक संघ की मौजूदगी का ज़िक्र किया था कि कैसे वह वहाँ चार्टर स्कूलों की अनुपस्थिति को प्रभावित करता है। अमरीका के विभिन्न राज्यों में शिक्षक सरकार

8. चार्टर समर्थक समूहों की बहस के लिए देखें— https://www.newschoolsforneworleans.org/education-in-nola/by-the-numbers/

9. माइक्रोसॉफ्ट वॉशिंगटन में लगभग 50,000 लोगों को रोज़गार देता है।

https://www.builtinseattle.com/2018/11/12/microsoft-redmond-campus-headquarters;

अमेज़ॉन केवल सीएटल में ही वर्तमान में 45,000 लोगों को रोज़गार दे रहा है।

https://komonews.com/news/local/amazon-moving-entire-worldwide-operations-team-from-bellevue-to-seattle

10. इस सूची में वॉशिंगटन 16वें स्थान पर है। 15 राज्य वॉशिंगटन से भी ज़्यादा कर इकट्ठा करते हैं जबकि वाशिंगटन सूचना प्रौद्योगिकी का केन्द्र है।

की शिक्षा नीति और नए नीतिगत बदलावों को कैसे देखते हैं?

हीथर : पाँच-छह ग़रीब राज्यों जैसे कि पश्चिमी वर्जीनिया, उत्तर कैरोलाइना और एरिज़ोना में शिक्षक 'रेड फ़ॉर एड' बैनर तले संगठित हुए। उन्होंने हड़ताल कर शिक्षा के लिए ज़्यादा बजट निर्धारित करने की माँग उठाई ताकि विद्यार्थियों को सहायता सेवाएँ देने के लिए लचीले कोष में अधिक पैसा उपलब्ध हो और वेतन में 10% बढ़ोतरी हो। मेरे राज्य एरिज़ोना ने शिक्षा के लिए पैसा देने का वायदा तो किया, पर करों को बढ़ाने से इन्कार कर दिया। और फिर उन्होंने ग़रीब बच्चों के लिए बने शिशु-विद्यालयों (preschools) का पैसा काट लिया। सेवानिवृत्त सैनिकों के गृह निर्माण, स्वास्थ्य और मानसिक देखभाल के कार्यक्रमों से भी पैसा काटा गया है। सरकार एक समूह को दूसरे के ख़िलाफ़ भिड़ा रही है और लोगों को अपराधी महसूस करा रही है।

मनीष : इन बजट कटौतियों के क्या कारण हैं? और इन बजट कटौतियों का स्कूलों पर क्या असर आया है?

हीथर : बजट में कटौती साल 2008 की आर्थिक मन्दी का नतीजा है और यह अब भी 2008 के फण्डिंग स्तर से नीचे है। आर्थिक मन्दी के सबसे सघन चरण की तुलना में सरकार अब के समय में कम्पनियों से कम करों की उगाही कर रही है। राज्य बड़ी कम्पनियों को कैसे आकर्षित करते हैं? वे ऐसा निम्न करों के द्वारा करते हैं। आप कैसे लोगों को ग़रीब राज्यों की ओर स्थानान्तरण के लिए राज़ी करेंगे, जहाँ कोई स्कूल नहीं हैं, कोई सांस्कृतिक अवसर नहीं हैं, और जहाँ नस्ली हिंसा का इतिहास रहा हो?

मनीष : बजट में यह कटौतियाँ किस तरह शिक्षकों और उनके अध्यापन को प्रभावित करती हैं?

हीथर : अगर आप अध्यापकों को ज़्यादा वेतन दें तो आप उनसे कर भी ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। ज़्यादा वेतन के साथ वे उन समुदायों में रह सकेंगे जहाँ वे पढ़ाते हैं, घर और कार ख़रीद सकेंगे, एक मध्यमवर्गीय जीवनशैली अपना पाएँगे और करों का भुगतान करेंगे जो मध्यमवर्गीय जीवन के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सरकार मध्यम वर्ग का फिर से विकास करेगी, इसका सरकार वायदा तो करती है पर अब तक उसने ऐसा किया नहीं है। निम्न वेतन की वजह से शिक्षक अपना परिवार बढ़ाने में देरी करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा और आर्थिक सुरक्षा नहीं है। लोग कहते हैं, 'शिक्षण एक आह्वान / बुलावा / नियति (calling) है', इसलिए बहुत-से शिक्षक निम्न वेतन के साथ समझौता कर लेते हैं। इस दलील का अर्थ यह निकलता है कि हम आपको कम पैसा दे सकते हैं क्योंकि आप कुछ और करना ही नहीं चाहते। या फिर, आप अगर इतने कम पैसों में काम करने को तैयार नहीं हैं तो ज़ाहिर तौर पर आप शिक्षक होने के लिए 'नियत / उपयुक्त' नहीं हैं।

मेरे राज्य एरिज़ोना ने शिक्षा के लिए पैसा देने का वायदा तो किया, पर करों को बढ़ाने से इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने ग़रीब बच्चों के लिए बने शिशु–विद्यालयों (preschools) का पैसा काट लिया। सेवानिवृत्त सैनिकों के गृह निर्माण, स्वास्थ्य और मानसिक देखभाल के कार्यक्रमों से भी पैसा काटा गया है।

मनीष : भारत में बहुत–से लोग यह दलील देते हैं कि अध्यापन एक सरल काम है। यह केवल बच्चों के प्रबन्धन तक ही सीमित है। जेण्डर और शिक्षा के मेरे कोर्स में हम शिक्षण पेशे की लैंगिक संरचना में आए ऐतिहासिक बदलावों के बारे में अध्ययन करते

हैं, जिसे अध्यापन का महिलाकरण कहा जाता है।[11] अमरीका में इस समझ और इन बदलावों के बारे में आपका क्या कहना है?

हीथर : अध्यापन में तमाम तरह के कौशल की दरकार होती है। किसी कक्षा के ज़्यादातर समय अच्छे से काम करने के लिए अध्यापक को बेतहाशा ऊर्जा, कौशल और अनुभव की ज़रूरत होती है। यूटाह काफ़ी हद तक एक अनुदारपंथी / रूढ़िवादी राज्य है जहाँ अध्यापकों की बहुतायत है। अध्यापन को महिलाओं के लिए उपयुक्त पेशे की तरह देखा जाता है और यह माना जाता है कि उन्हें उनके अपने बच्चे हो जाने तक पढ़ाना चाहिए। औरतों पर 4–5 बच्चे पैदा कर एक बड़ा परिवार बनाने का दबाव रहता है। आमतौर पर ज़्यादा शिक्षक महिलाएँ हैं। यूटाह में प्रारम्भिक वेतन कम ही रहता है, क्योंकि नए शिक्षकों की बहुतायत है। लेकिन वेतन में वृद्धि ज़्यादा पुरुषों को शिक्षण कार्य की ओर ले आएगी। अमरीका में बहुत-से लोग यह शिकायत करते हैं कि शिक्षक कुछ ज़्यादा ही उदारवादी हैं। हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे ने शिक्षकों को 'हारे हुए' (losers) कहा, और यह दलील दी कि शिक्षक आमतौर पर समाजवादी[12] होते हैं। अनुदारपन्थी / रूढ़िवादी पुरुष अध्यापन के पेशे में नहीं जाते क्योंकि अध्यापन से मिली एक तनख़्वाह में वे अपने परिवार का गुज़ारा नहीं कर सकते। अनुदारपंथी / रूढ़िवादी महिलाएँ आमतौर पर पहला बच्चा हो जाने तक पढ़ाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा अनुदारपंथी अध्यापन के पेशे में आएँ तो आपको अनुदारपंथी पुरुषों को आकर्षित करने के लिए वेतन तो बढ़ाना पड़ेगा।

मनीष : हमने पढ़ा था कि अमरीका के शिक्षकों को पाठ्यचर्या और मूल्यांकन के सन्दर्भ में बहुत-सी स्वायत्तताएँ हैं। वर्तमान सन्दर्भ में यह किस प्रकार पुनर्गठित किया जा रहा है?

हीथर : जॉर्ज डब्लू बुश के शासन काल में 'कोई बच्चा पीछे न छूटे' (NCLB) लागू किया गया और राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासन काल में सबके लिए समान आधारभूत / अनिवार्य (core) और मानकीकृत परीक्षण लागू किया गया। उन्होंने शिक्षकों की स्वायत्तता को ख़त्म कर दिया है। अब एक नव-उदारवादी बदलाव आया है जिसमें पाठ्यक्रम अच्छे विद्यार्थी और अच्छे नागरिक बनाने के बारे में होने की बजाय नौकरी पाने के लिए तैयारी, गणित और अँग्रेज़ी, और कुछ मामलों में विज्ञान पर केन्द्रित है।

11. अध्यापन पेशे के 'महिलाकरण' से अभिप्राय अध्यापन के पेशे की संरचना में आए उन बदलावों से है जिनके चलते महिलाएँ अध्यापन पेशे का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा बन गई हैं। 'महिलाकरण' के साथ जुड़े विभिन्न पहलुओं में अध्यापन पेशे में संलग्न महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत, इस प्रतिशत वितरण के प्रभाव, महिलाओं के इस पेशे में पहुँचने की दर इत्यादि को देखना शामिल है (केलहर 2011:1)। कोनरीना और रोमन (2006) और एप्पल (2011) यह तर्क देते हैं कि पेशे के तौर पर अध्यापन को हमें ऐतिहासिक रूप से देखने की ज़रूरत है। ख़ासकर उन राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक कारकों को ध्यान से देखे जाने की ज़रूरत है जिनके तहत बड़ी संख्या में महिलाएँ अध्यापन कार्य से जुड़ीं और पुरुषों ने अध्यापन को छोड़ा। पितृसत्तात्मक सम्बन्धों में महत्त्वपूर्ण बदलावों और विचारधारात्मक परिवर्तनों के साथ, अध्यापन को महिलाओं के काम और घरेलू जीवन में उनके पालन-पोषण और देखभाल के 'प्राकृतिक' कामों के विस्तार के तौर पर देखा जाने लगा। एप्पल (2011) इस बात पर ज़ोर देते हैं कि इन आर्थिक और विचारधारात्मक बदलावों के साथ अध्यापन अब पहले जैसा पेशा नहीं रहा। वे अवकौशलीकरण (deskilling), ज़्यादा कड़े नियन्त्रण, पेशे में प्रबन्धकीय भूमिकाओं तक पहुँचने की सम्भावनाओं में कमी और वेतन के घटने को इन परिवर्तनों के साथ जोड़ते हैं। जबकि पहले महिलाओं और अध्यापन के 'महिलाकरण' पर चर्चा अमरीका, कनाडा, इंग्लैण्ड, न्यूज़ीलैण्ड और ऑस्ट्रेलिया पर केन्द्रित थी, हाल के वर्षों में दक्षिण अमरीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ़्रीका इस बहस के दायरे में आए हैं। इन क्षेत्रों की तुलना में भारत में महिला अध्यापिकाओं की कमी रही है। हालाँकि, यह तस्वीर अलग-अलग राज्यों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, निजी एवं सरकारी विद्यालयों और प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर एक-सी नहीं है। भारत पर अध्ययनों के लिए देखें— केलहर (2011) और कथूरिया (2016)।

12. https://www.washingtonpost.com/education/2019/02/16/why-donald-trump-jr-loser-teachers-comment-was -a-hilling-moment-educators-around-world/?utm_term=.65887e69207

बहुत-से लोगों ने बच्चों के विकास में भागीदारी निभाने की दृष्टि से अध्यापन कार्य को चुना, जिसे अब ख़त्म किया जा रहा है। अध्यापकों से यह माँग की जा रही है कि वे अपनी नौकरी बरक़रार रखने के लिए बच्चों का परीक्षा में अच्छे अंक लाना सुनिश्चित करें। इस स्थिति ने भ्रष्टाचार काण्ड को भी जन्म दिया है। सन् 2000 के आरम्भ में एटलांटा (जॉर्जिया) में अध्यापक छात्रों के अंक बढ़ाने के लिए ख़ुद ही उत्तर पुस्तिकाएँ भर रहे थे। यह नस्लवादी भी था क्योंकि एटलांटा (जॉर्जिया) में अधिकांश शिक्षक और विद्यार्थी अश्वेत हैं। यह विमर्श, अश्वेत लोग बेईमान होते हैं, के विमर्श में तब्दील हो गया। ऐसा कहा जाने लगा कि वे अपनी योग्यता के दम पर ख़ुद को नहीं बना सकते, इसलिए बेईमानी करते हैं। इस तरह यह योग्यता पर नस्लवादी विमर्श था।

मनीष : भारत में बहुत-से लोग यह तर्क देते हैं कि अगर अध्यापक मेहनत और लगन से पढ़ा रहे हैं तो उन्हें अपने शिष्यों के अध्ययन परिणामों की जाँच से डरने की ज़रूरत नहीं है।

हीथर : अध्यापक मूल्यांकन या आकलन किए जाने से नहीं डरते हैं, पर वे इसे उस रूप में चाहते हैं जिससे विद्यार्थियों का सीखना और उनका अध्यापन बेहतर हो सके। लेकिन मानकीकृत मूल्यांकन केवल एक ही तरह के खाँचे को देखता है और उसी का महत्त्व है। यह श्रेणी पर मूल्यांकन नहीं करता है या आकलन की प्रक्रिया पर कि आप कैसे आकलन करते हैं या फ़ीडबैक देते हैं। इन मानकीकृत परीक्षाओं को बिल्कुल भी अन्दाज़ा नहीं होता कि विद्यार्थी किन परिस्थितियों से आते हैं और उन्होंने स्वयं में कैसे सुधार किया है। अध्यापकों के पास कोई ज़रिया भी नहीं होता यह बताने के लिए कि छात्रों का कैसे और क्या आकलन किया जाए। उन्हें केवल आकलन के मानदण्ड दे दिए जाते हैं। केवल परीक्षा के लिए अध्यापन शैक्षिक और बौद्धिक रूप से परिपूर्णता देने वाला पेशा नहीं रह जाता जैसा मैंने इसकी कल्पना की थी।

सन्दर्भ

Apple, M (2011). *Teaching and "Women's work": A comparative and historical analysis.* In Richard Arum, Irennee R Beattie and Karly Ford (Eds), *The structure of schooling: Readings in the sociology of education* (pp. 371-381). Newbury Park, CA: Pine Forge Press.

Cortina, R & Román, S S (2006). *Women and teaching: Global perspectives on the feminization of a profession.* New York: Palgrave Macmillan.

Hursh, D (2007). *Assessing no child left behind and the rise of neoliberal education policies.* American Educational Research Journal, 44(3), 493-518.

Kathuria, Arushi (2016). *Who is a Teacher: An Insight into their Changing Social Profile.* MA in Education Thesis. Delhi: School of Education Studies, Ambedkar University Delhi.

Kelleher, F (2011). *Women and the teaching profession: Exploring the feminisation debate.* London: Commonwealth Secretariat and UNESCO.

National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) (2018). *School Education in India: U-DISE Flash Statistics 2016-17*. New Delhi: National Institute of Educational Planning and Administration.

Slee, R, Weiner, G, & Tomlinson, S (1998) (Eds). *School effectiveness for whom?: Challenges to the school effectiveness and school improvement movements.* London: Falmer Press.

Smith, J M & Kovacs, P E (2011). *The impact of standards based reform on teachers: The case of 'No child left behind'.* Teachers and Teaching: Theory and Practice, 17(2), 201-225.

Wells, A S, Slayton, J, & Scott, J (2002). *Defining democracy in the neoliberal age: Charter school reform and educational consumption*. American Educational Research Journal, 39(2), 337-361.

Wrigley, T (2013). *Rethinking School Effectiveness and improvement: a question of paradigms. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 34(1), 31-47.*

Wun, C (2014). *The anti-Black order of no child left behind: Using Lacanian psychoanalysis and Critical race theory to examine NCLB.* Educational Philosophy and Theory, 46(5), 462-474.

डॉ. मनीष जैन एक दशक तक विद्यालय स्तर पर पढ़ाने के बाद अब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ़ एजुकेशन स्टडीज़ से जुड़े हैं। उनका अध्यापन और शोध शिक्षा के इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति के चौराहे पर केन्द्रित है।
सम्पर्क : manish@aud.ac.in

इस साक्षात्कार का सह–लेखन रूमा दत्त ने किया है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में जर्मन पढ़ाती हैं। फ़िलहाल 'आप्रवासी स्वः 1990 उत्तरोत्तर हिन्दी और तुर्की-जर्मन सिनेमा का तुलनात्मक अध्ययन' विषय पर पीएचडी शोध-प्रबंध लिख रही हैं।